MP Specific October Month Current Affairs

सायबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2021 समारोह का समापन

- प्रदेश पुलिस अकादमी में आयोजित 10 दिवसीय सायबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2021 के समापन हुआ |
- इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल श्री मंगुलाल भाई पटेल ,सी बी आई पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला उपस्थित थे |
- सायबर सुरक्षा कानूनों का कड़ाई से पालन करने के साथ ही पीड़ित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता पर जोर दिया जाना साथ ही सायबर क्राइम के संबंध में थाना स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है।

भोज मुक्त विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह

- भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के 29वें वर्ष में पहली बार स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यकम में माननीय राज्यपाल मंगुलाल भाई पटेल सम्मलित थे |
- इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी जिलों में सर्वसाधन सम्पन्न अग्रणी महाविद्यालय और सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक महाविद्यालय स्थापित किए जाएँगे।
- विद्यार्थियों को कोर्सो के संबंध में प्रवेश से पूर्व जानकारी देने और कैरियर गाइडेंस की व्यवस्था करने के लिए कहा गया |

गांधी जयन्ती पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन

- वर्ष 2019 के लिए हरिद्वार की संस्था 'अखिल विश्व गायत्री परिवार' और वर्ष 2020 के लिए उस्मानाबाद की संस्था 'भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान' को सम्मान प्रदान किया गया |
- राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान के अन्तर्गत प्रत्येक संस्था को दस लाख रुपये की आयकर मुक्त राशि, सम्मान पट्टिका, शॉल व श्रीफल से सम्मानित किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना और अमृत योजना

- स्वच्छ भारत मिशन(शहरी)2.0 का उद्देश्य शहरों को कचरा मुक्त बनाना है |

- इसी तरह अमृत मिशन-2.0 का प्रमुख उद्देश्य जल सुरक्षित शहर बनाना है । जिसके अंतर्गत सीवेज का उत्कृष्ठ प्रबंधन और नदी, तालाब जैसी जल संरचनाओं में जाने वाले गंदे पानी को रोकना है।

जल जीवन मिशन- घर घर में नल से जल

- मिशन के माध्यम से गाँव-गाँव नलजल योजनाओं के माध्यम से हर घर में नल से शुद्ध जल देना सुनिश्चित किया जा रहा है।
- जिन ग्रामों में जल स्रोत उपलब्ध नहीं है, वहाँ नवीन जल स्रोत विकसित कर नलजल योजना शुरू की जाएगी।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ग्रामीण आबादी विशेषकर महिलाओं को पेयजल समस्या से निजात दिलाने हेतु 15 अगस्त 2019 को जल मिशन की घोषणा की गई ।
- इस मिशन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में आवंटन किया जा रहा है ।
- मिशन के माध्यम से जून 2020 से प्रदेश में गाँवों के हर घर में नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाया जा रहा है ।
- इस मिशन अंतर्गत जन-भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है, जिससे ग्रामीणों में नलजल योजना में अपनत्व बना रहे।

मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय वन्य -प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया

- राज्य-स्तरीय वन्य-प्राणी सप्ताह के अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में आयोजित हुए पक्षी दर्शन एवं प्रकृति शिविर में तकरीबन 65 पक्षी प्रेमियों ने पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को प्रस्तुत किया गया |
- इनमें गोल्डन ओरिओल, दूधराज, इग्रेट, मेग पाई राबिन, ब्रोंज विंग जकाना, किंगफिशर, ग्रीन बी ईटर, टिटहरी, पोंड हेरोन, रेड मुनिया, आईओरा, विहिस्लिंग टील्सकार्मोरेंट, मूरहैन, ड्रोंगो, सिल्वर बिल मुनिया जैसी कई प्रमुख प्रजाति के पक्षी शामिल हैं।
- ग्रे पेनसी कॉमन ईवनिंग ब्राउन, प्लेन टाईगर, कॉमन ग्राम यलो, ब्लू टाइगर, क्रीमसन रोज आदि शामिल हैं।

'साथी' योजना लागू करने में मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य

- ''साथी (सस्टेनेबल एग्रिकल्चर थ्रू होलिस्टिक इन्टीग्रेशन) परियोजना'' लागू करने में मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य होगा।
- यह परियोजना के किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य की पूर्ति में लाभदायक सिद्ध होगी |

- व्यावहारिक रूप से यह योजना किसानो को अधिक लाभ पहुंचाएगी |
- प्रारंभ में यह योजना पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 5 जिलों के 10 विकासखण्डों में लागू होगी।
- ''साथी'' योजना प्रथम चरण में प्रदेश के 26 जिलों गुना , सतना, अशोकनगर, ग्वालियर, रीवा, मुरैना, अलीराजपुर, बालाघाट, बड़वानी, छतरपुर, धार, पन्ना, राजगढ़, श्योपुर, शहडोल, शिवपुरी, टीकमगढ़, झाबुआ, सीहोर, कटनी, रायसेन, अनूपपुर, सिवनी, देवास, उमरिया सहित दमोह के 100 विकासखण्डों हेतु बनाई गई है।
- इस योजना के 5 घटक साथी कृषक समूह, साथी प्र-संस्करण केन्द्र, साथी उद्योग, साथी बाजार तथा कॉमन फेसिलिटी सेंटर होंगे।

स्वामित्व योजना

- स्वामित्व योजना को देश के जिन 9 राज्यों में पायलेट आधार पर लागू किया गया है, उसमें मध्यप्रदेश भी शामिल है।
- स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन तीन चरणों में 10-10 जिलों को शामिल कर क्रमबद्ध रूप से प्रारंभ किया गया हैं।
- इस योजना के अंतर्गत सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से ग्रामों के रहवासी क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से नक्शे का निर्माण तथा डोर-टॅ-डोर सर्वे कर अधिकार अभिलेखों का निर्माण किया जा रहा है।
- मध्यप्रदेश के 42 जिलों में इस योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से कार्य किये रहे है |

स्वामित्व योजना से लाभ :

- ग्राम की रहवासी भूमि में स्वयं का मकान बनाकर निवास करने वाले ग्रामवासियों को अपने घर का मालिकाना हक मिल सकेगा।
- आबादी भूमि संबधित कागजात मिल जाने से कानूनी सहायता आसानी से मिल सकेगी |
- स्वेक्षा से घर बनाने तथा अतिक्रमण की समस्या से निजात मिलेगी।
- सम्पत्ति का रिकार्ड हो जाने से बैंक ऋण लेने में आसानी होगी ।
- भूमि संबंधी विवाद भी खत्म होंगे।
- जमीन एवं भवन के नामांतरण आसानी से हो सकेंगे |

जन कल्याण एवं सुराज अभियान

- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जन-कल्याण और सुराज अभियान में अक्टूबर प्रथम सप्ताह में मिन्टो हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम जनसेवा और मोबाइल गवर्नेंस सेवाओं के बारे में बैठक आयोजित की गई ।
- प्रदेश के नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिन -प्रतिदिन की उपयोगी सेवाएँ सुगम और सरलता से उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है।
- 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर 2021 लगातार 21 दिन तक संचालित यह जन-कल्याण और सुराज अभियान ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम की दिशा में अहम भूमिका निभाई है |
- लगातार 21 दिन चले इस अभियान में किसान, मजदूर, महिला, असहाय और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम कर हितग्राहियों को हितलाभ वितरण के साथ अनेक योजना संबधी लाभ पहुचाये है

जनसुविधाओं को बढ़ावा देने बड़ी ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र स्थापित

- प्रदेश के नागरिकों को उनके द्वार पर सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। नागरिकों को खसरा की प्रति सिर्फ 10 रूपये प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी।
- यह सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर मोबाइल नंबर से मेसेज भेजने से शुरू हो जाएगी |
- इन पोर्टल से नागरिकों को मिलने वाली जन सुविधाएं बढ़ेंगी और उनके कार्य सुगमता से होंगे।

ई-रुपी व्यवस्था ई-वाउचर के रूप में लागू होगी

- प्रदेश में "ई-रुपी" की व्यवस्था को ई-वाउचर के रूप में लागू की गई है |
- आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों की उपचार राशि एवं छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए "ई-रुपी" के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक अकाउंट में जमा किये जा रहे है |

प्रदेश में 4 से10 अक्टूबर तक "आइकॉनिक सप्ताह'' का आयोजन

- आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश में 4 से10 अक्टूबर तक "आइकॉनिक सप्ताह'' के रूप में मनाया गया |
- सप्ताह में मध्यप्रदेश में भी पर्यावरण, तालाब संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने संबंधी विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गए |

- प्रदेश की रामसर साइट भोज वेटलैण्ड (बड़ा तालाब भोपाल) पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया |

राज्य में कमर्शियल वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप और रियर मार्किंग प्लेट अनिवार्य

- बिना मानक गुणवत्ता के रिफ्लेक्टर टेप (परावर्ती पट्टिकाओं) वाले कामर्शियल वाहनों के लिए अब फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जायेंगे |
- इस संबंध में लिखित दस्तावेज जारी कर इस प्रक्रिया को पूर्ण कम्प्यूटीकृत किया जा रहा है।
- वाहन निर्माताओं के अधिकृत डीलरों द्वारा वाहन पर लगाये गए रिफ्लेक्टर टेप का सर्टिफिकेट पोर्टल के माध्यम से ही जनरेट होकर प्रिंट हो सकेगा।
- सर्टिफिकेट पर वाहन पर लगाये गए रिफ्लेक्टर टेप की विस्तृत जानकारी जैसे लम्बाई, चौड़ाई, रंग, टेप का निर्माण वर्ष, कोड, निर्माता का नाम तथा वाहन की जानकारी, जैसे वाहन पंजीयन क्रमांक, चेचिस नम्बर, इंजन नम्बर, वाहन श्रेणी, वाहन की बॉडी का प्रकार आदि अंकित रहेगा।
- वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने के पूर्व सम्बधित आरटीओ को पोर्टल के माध्यम से रिफ्लेक्टर टेप/रियर मार्किंग प्लेट फिक्सेशन सर्टिफिकेट की जाँच करना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा।
- वाहन जाँच के समय प्रर्वतन अमला/पुलिस सर्टिफिकेट पर अंकित क्यूआर कोड और पोर्टल के माध्यम से सर्टिफिकेट की जाँच कर सर्टिफिकेट की सत्यता जाँच कर सकेंगे।
- इस प्रक्रिया से किसी भी वाहन पर अमानक स्तर के रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर टेप, रियर मार्किंग प्लेट लगाया जाना संभव नहीं होगा, जिससे निश्चित रूप से वाहन दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

राज्य में वाहनों में नंबर प्लेट संबधी नवीन व्यवस्था

- इस व्यवस्था के अंतर्गत वाहन मालिक पुराने 4 पहिया वाहनों के आवंटित नंबर का उपयोग अपने नए वाहनों के लिए कर सकेंगे।
- इस हेतु वाहन मालिक को पुराने नंबर के लिए दी गई राशि अथवा न्यूनतम 15 हज़ार रूपये में जो भी अधिक होगा, भुगतान करना होगा।
- राज्य शासन द्वारा की गई इस नवीन व्यवस्था का सीधा लाभ वी.आई.पी नम्बर लेने वाले वाहन मालिकों को मिल सकेगा।

ड्राइविंग लाइसेंस संबधी प्रक्रिया को सरल किया गया

- ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को और अधिक सरल किया गया है।

BYJU'S EXAM PREP

SUBSCRIBE BYJU'S EXAM PREP

- कोई भी आवेदक लर्निंग लाइसेंस, नवीन ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन, नवीनीकरण अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में अन्य श्रेणी के आवेदन के साथ रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 1ए में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे।
- एक अप्रैल 2021 के पूर्व उक्त मेडिकल सर्टिफिकेट मैनुअल तरीके से जारी किए जाने का प्रावधान था।

विद्युत् ठेकेदारों के लायसेंस ऑनलाइन

- ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत ठेकेदारों हेतु जाने की व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से लाइसेंस जारी किये गए है।

विशेषताएँ :

- लाइसेंस जारी किये जाने की संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस व्यवस्था के रूप में ऑनलाइन प्रक्रिया होगी |
- निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन माध्यम से वांछित लाइसेंस प्राप्त किये जायेंगे |
- कार्य की प्रगति की स्थिति से आवेदक को मोबाइल पर एसएमएस एवं व्हाट्सऐप के माध्यम से सूचित किया जायेगा |
- ई-साइन के माध्यम से सभी जानकारी जारी किये जाने की सुविधा होगी ।
- समय-सीमा में प्रकरण का निराकरण न होने की स्थिति में उच्च अधिकारियों को नोटिफिकेशन जारी किये जाने की सुविधा होगी ।

आईएसएसएफ शूटिंग जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप

- आईएसएसएफ शूटिंग जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आयुषी पोद्दार, सुश्री निश्चल और भोपाल की बेटी प्रसिद्धि महंत को सिल्वर मेडल जीतने पर हार्दिक बधाई दी है।

गाडरवारा की तुअर दाल और करेली गुड़ से प्रदेश को मिलेगी विशेष पहचान

- आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश अभियान में 'एक जिला-एक उत्पाद' में गाडरवारा की तुअर दाल और करेली के गुड को मध्यप्रदेश की विशिष्ट पहचान बनाने के लिए सतत प्रयास जारी हैं।
- गाडरवारा तुअर दाल अपने सौंधेपन एवं स्वाद के लिए जानी जाती है।
- करेली का गुड़ भी स्वाद और सेहत के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखता है।

ऑनलाइन जन सेवाओं का प्रदेश में विस्तार

- प्रतिवर्ष औसत रूप से 15 से 20 विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हेतु मध्यप्रदेश से चुने जाते हैं।
- प्रदेश में पहली बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 38 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है।
- सफलता के मंत्र कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के लाखों विद्यार्थी इसमें जुड़ सकेंगे|

सिवनी बालाघाट में वर्चुअल कार्यशाला में दिव्यांग जनों प्रमाण प्रत्र बनाये गए

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगता के प्रमाणीकरण के लिए सिवनी एवं बालाघाट जिले के मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के अधिकारी एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रुप से वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन आयुक्त निःशक्तजन कार्यालय एवं क्षेत्रीय दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र भारत सरकार एवं साइट सेवर्स संस्था के सहयोग से आयोजित किया गया।

वन के परिस्थितिकीय तंत्र को समझने हेतु "अनुभूति" कार्यक्रम की शरुआत

- ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा "अनुभूति" कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 3 लाख 20 हजार स्कूली छात्रो को शामिल किया जाएगा|
- पहली बार अशासकीय विद्यालयों के 2 लाख विद्यार्थियो को "न लाभ-न हानि" के आधार पर शुल्क प्राप्त कर अनुभूति शिविरों से जोड़ा जाएगा।
- शासकीय स्कूलों हेतु यह शिविर माह दिसम्बर 2021 से प्रारंभ होकर मार्च 2022 तक आयोजित होंगे।
- इस कार्यक्रम में वन के परिस्थितिकीय तंत्र के घटकों की व्याख्या, पर्यावरण, वन संरक्षण, जैव औषधि और वन प्रबंधन की सामान्य जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण परिषद् का गठन

- राज्य शासन ने आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश-2023 के संकल्प के अनुरूप राज्य-स्तरीय पर्यावरण परिषद का गठन किया गया है।
- यह परिषद प्रदेश के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की नवीन परियोजनाओं के निर्माण हेतु रणनीतिक सुझाव, मार्गदर्शन, परामर्श और नवाचार को प्रोत्साहित करेगी।

- परिषद पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक सम्पदा के संवहनीय उपयोग के लिये किये जा रहे प्रयासों और विभिन्न विभागों द्वारा पर्यावरण से संबंधित सतत विकास लक्ष्य के कार्यों की भी जांच करेगी।

"अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास" का ग्वालियर में गठन

- ग्वालियर में स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के निर्माण और संस्कृति विभाग के आधीन स्वायत्त "अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास'' का गठन किया जायेगा |
- इस स्मारक न्यास के माध्यम से युवाओं और नौनिहालों में राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र विकास के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरुकता का प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रयास किये जायेंगे |
- राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र विकास के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने हेतु फिल्मों का संग्रहण, दृश्य श्रव्य/मल्टीमीडिया, संग्रहालय, मुक्ताकाश मंच एवं ऑडिटोरियम आदि सुविधाओं का सृजन, उनकी बौध्दिक प्रखरता, साहित्यिक के माध्यम से प्रसारित किया जायेगा |

लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन

- इसके अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक आंगनबाड़ी एवं पंचायत भवनों में वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित होगा और बालिकाएँ जुड़ेंगी। कार्यक्रम को वेबकास्ट लिंक दूरदर्शन, आकाशवाणी, जनसंपर्क के ट्विटर, फेसबुक पर लाइव तथा महिला बाल विकास विभाग के सभी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर प्रसारित किया जाएगा।
- बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2007 को लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई।

लाड़ली लक्ष्मी योजना-2

- ऐसी बेटियाँ भी, जिन्हें कहीं कोई छोड़ गया या जिनका कोई नहीं है, उन्हें भी लाड़ली लक्ष्मी माना जाएगा और योजना का लाभ दिया जाएगा।
- बेटियों के जन्म की संख्या के आधार पर लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली ग्राम पंचायत/ग्राम घोषित किया जायेगा ।
- 18 वर्ष की आयु होने पर प्रत्येक लाड़ली लक्ष्मी को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पी.एम. गति शक्ति मास्टर प्लान

- यह योजना वर्तमान भारत को गति एवं शक्ति प्रदान करेगी , "नेक्स्ट जनरेशन इन्फ्रास्ट्र-क्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी" से देश को प्रगति की एक ओर दिशा मिलेगी।

- गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफार्म है जो एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के एक साथ किये जा रहे कियान्वयन से रेल और सड़क मार्ग सहित 16 मंत्रालयों को एकसाथ लेकर आएगा |

श्री रवि विजयकुमार मलिमुठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधिपति नियुक्त

मध्य प्रदेश मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायधिपति के रूप में श्री रवि विजयकुमार मलिमठ को नियुक्त किया गया , राज्यपाल श्री मनुभाई पटेल द्वारा शपथ दिलवाई गई |

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में जनजाति पारम्परिक भोजन “जायका” की शुरुआत

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल द्वारा संग्रहालय भ्रमण पर आने वाले दर्शकों की मांग पर भील जनजाति के पारंपरिक भोजन कार्यक्रम “जायका” की शुरूआत की गयी है।
- मध्यप्रदेश के भील जनजाति का पारंपरिक भोजन मक्का की रोटी, बैगन का भुर्ता, धनिया, लेहसुन की चटनी, गुड आदि पारंपरिक व्यंजनों की उपलब्धता होगी ।
- **मक्के की रोटी** में फाइबर होता है, जो पाचन संबंधी समस्याओं से राहत पाने में मदद करता है।
- यह शरीर में कॉलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में सहायक होता है। साथ ही फाइबर युक्त आहार लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है।

मध्यप्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं के मकान हेतु महत्वपूर्ण प्रयास

- प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 21 लाख 5 हजार आवास बनाये जा चुके है |
- मध्यप्रदेश की तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, सहरिया और भारिया हेतु विशेष परियोजना के अंतर्गत आवास गृह प्रदान किये गए हैं।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में हर गरीब परिवार को भूमि का पट्टा और पात्रतानुसार आवास निर्माण की राशि दी जाएगी।
- आवास निर्माण की अवधि राष्ट्रीय स्तर पर 114 दिवस है। देखा जाये तो मध्यप्रदेश में अच्छी गति के साथ आवास निर्माण के कार्य पूर्ण किये हैं।

जीवदया गौसेवा सम्मान पुरस्कार

- मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में 20 अक्टूबर को जीव दया सम्मान पुरुस्कार का आयोजन किया गया , इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं आचार्य श्री विद्यासागर उपस्थित रहे |

BYJU'S EXAM PREP

SUBSCRIBE BYJU'S EXAM PREP

- इस कार्यक्रम में प्रदेश की उत्कृष्ट गौशालाओं और पशुओं के प्रति सेवाभावी संस्थाओं और व्यक्तियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया |
- संस्थागत श्रेणी में कुल 7 पुरस्कार दिये गए । प्रथम, द्वितीय, तृतीय के साथ 4 सांत्वना पुरस्कार दिये जाने हैं, जिनकी राशि क्रमश: 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 50-50 हजार है। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार में क्रमश: एक लाख, 50 हजार और 20 हजार की राशि प्रदान की की गई |

प्रदेश के इंदौर शहर में ट्रांसमिशन सिस्टम में हाइब्रिड स्विच गियर मॉडयूल सिस्टम का प्रयोग

- मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने प्रदेश के इंदौर शहर में पहली बार ट्रांसमिशन सिस्टम के विस्तार में हाइब्रिड स्विच गियर मॉडयूल सिस्टम का उपयोग किया है।
- इंदौर ईस्ट स्थित 220 केवी सब स्टेशन बिचोली में ट्रांसमिशन कंपनी ने 50 एमवीए क्षमता का एक नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। इसमें हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल सिस्टम का प्रदेश में पहली बार इस्तेमाल किया गया।
- प्रदेश में पहली बार इंदौर में कम जगह पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया तथा सब स्टेशन में अंडरग्राउंड केबल का इस्तेमाल किया गया ।
- इसमें ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेने वाले सिस्टम को 33 केवी वोल्टेज लेवल पर अंडरग्राउंड इंसुलेटेड केबल के माध्यम से जोडा गया।
- मध्यप्रदेश में पहली बार 33 केवी के मेन सिस्टम के लिए इस तरह की उच्च क्षमता की इंसुलेटेड केबल का उपयोग किया गया है।
- सब स्टेशनों के निर्माण और विस्तारीकरण के लिए यह मॉडल लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता पर आधारित है।

संबधित तथ्य :

- हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किसी पारंपरिक सब स्टेशन में विस्तार या बदलाव के लिए किया जा सकता है।
- इसमें एयर इंसुलेटेड स्विच गियर और अत्याधिक विद्युत प्रतिरोधक क्षमता वाली सल्फर हेक्साफ्लोराइड आधारित गैस स्विचगियर की तकनीक वाले उपकरणों को एक ही मॉडल के माध्यम से उपयोग में लाया जाता है।
- यह हाइब्रिड तकनीक सब स्टेशनों में उपयोग होने वाली जगह में 50% तक की कमी लाता है जो कि नई स्थापना या विस्तारीकरण के लिए सही और विश्वसनीय लागत है|
- आने वाले समय में मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ऐसे अनेक जरुरतमंद सब स्टेशनों में उपयोग किया जा सकेगा।
- इससे घनी आबादी में स्थापित सब स्टेशनों में विद्युत आपूर्ति का एक और विकल्प उपलब्ध हो सकेगा।

विद्युत् दरों में 20 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी

- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरो में 20 हजार करोड़ रूपये से अधिक की सब्सिडी दी जाएगी ।
- घरेलू उपभोक्ताओं के लिये लागू योजना में 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर प्रथम 100 यूनिट तक अधिकतम 100 रुपये का देयक दिए जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बी.पी.एल. घरेलू उपभोक्ता, जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट है, से मात्र 25 रूपये प्रति माह के मान से 4 माह में 100 रूपये लिए जाने का प्रावधान रखा गया है |
- 10 हॉर्सपावर तक की क्षमता के मीटर रहित स्थायी कृषि पम्प उपभोक्ता को 750 रूपये प्रति हॉर्सपावर प्रति वर्ष की फ्लैट दर देय होगी।
- 10 हॉर्सपावर से अधिक की क्षमता के मीटर रहित स्थाई कृषि पंप उपभोक्ता से 1500 रूपये प्रति हॉर्सपावर प्रति वर्ष की फ़्लैट दर देय होगी।
- एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हॉर्सपावर तक के अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदान की जायेगी।
- उच्च दाब उदवहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार तथा वार्षिक न्यूनतम प्रभार में छूट दी जायेगी।

''मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार'' योजना को स्वीकृति

- गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकासखण्डों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्राम से राशन सामग्री वितरण की योजना **"मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार''** प्रारंभ की गई है |
- यह योजना उप चुनाव निर्वाचन आचार संहिता के जिलों को छोड़कर शेष जिलों के आदिवासी विकासखण्डों में माह नवम्बर, 2021 से लागू की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत 16 जिलों के 74 विकासखंण्ड में 7511 ग्राम के जनजातीय परिवारों को लाभ मिलेगा |
- एक वाहन द्वारा एक माह मे औसतन 22 से 25 दिवस (अवकाश छोड़कर) 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी ।

कठपुतली कला पर आधारित पुतुल समारोह का आयोजन

- मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में कठपुतली कला की विविध शैलियों पर चार दिवसीय एकाग्र 'पुतुल समारोह' (20 से 24 अक्टूबर 2021) का आयोजन किया गया |
- पुतुल समारोह में कठपुतली के माध्यम से ऐतिहासिक और पौराणिक चरित्रों एवं कथा-कहानियों को दिखाया जाता है।
- वर्तमान समय में इस कला में समकालीन विषयों को भी आधार रूप में ग्रहण किया गया है, जिससे युवा पीढ़ी को सदियों से चली आ रही इस विधा और इसके माध्यम से जीवन मूल्यों को संरक्षित करने की विधि को बताया जा सके।

शासकीय सेवकों तथा स्थाई कर्मी को देय महंगाई भत्ते की दर में 8 प्रतिशत वृद्धि

- वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों तथा स्थाई कर्मी को देय महंगाई भत्ते की दर में अक्टूबर 2021 से 8 प्रतिशत वृद्धि की गई है |
- महंगाई भत्ता दर में 8% की वृद्धि सातवें वेतनमान के अनुसार 20 प्रतिशत मंहगाई भत्ता के रूप में देय होगी |
- जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप देय एरियर्स का भुगतान दो बराबर किश्तों में किया जाएगा। पहली किश्त का भुगतान नवंबर 2021 में होगा और दूसरी किश्त का भुगतान मार्च 2022 में होगा।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन

- “प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन" प्राथमिक, माध्यमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्य ढाँचे और मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
- "पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन" के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ -साथ नागरिकों को सरल, सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- मिशन में सम्पूर्ण देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को उच्च स्तर बनाया जा सकेगा। साथ ही समाज के सभी वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा सकेंगी।

सीएम राइज योजना

- शिक्षा के क्षेत्र में इस योजना के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में सुधार करना और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए स्कूलों को सक्षम बनाना है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में प्रदेश में 9 हजार 200 सुविधायुक्त 'सीएम राइज स्कूल' प्रारंभ होंगे। इसके लिए बजट में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- इसके अंतर्गत विद्यार्थियों हेतु व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी होगी, जिससे शिक्षा के साथ विद्यार्थी आर्थिक समझ विकसित कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

- ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए आवसियाभु खंड नहीं है, उन्हें सरकार रहने के लिए नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गतग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आवंटन के दिशा-निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं।
- राज्य सर्कार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत मेंरहवासी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू खंड उपलब्ध कराने हेतु भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई |
- आवंटन के लिए भू-खण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर होगा। परिवार से आशय पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री होंगे। आवेदन करने के लिए वही आवेदक परिवार पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी हों। आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन SAARA पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- भू अधिकार योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम से उपलब्धता के आधार पर भू-स्वामी अधिकार-पत्र दिए जायेंगे |
- इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार पात्र नहीं होंगे – 1 जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए मकान है | **2** परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है 3 जो परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है 4 यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता या परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है 5 यदि आवेदक ऐसे ग्राम का आवासीय भू खंड चाहता जहाँ उसका नाम जनवरी 2021 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे |

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केन्द्र सरकार की योजना है, इसके अंतर्गत लोगों को विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों के लिये 50 हजार से 10 लाख रूपए तक का ऋण दिया जाता है।
- इस योजना में वाणिज्यिक बैंक, आर.आर.बी, एम.एफ.आई, एन.बी.एफ.सी और लघु वित्त बैंकों द्वारा मुद्रा ऋण दिये जाते हैं।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर जिला, ब्लॉक स्तर पर बैंकों द्वारा 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया |

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन

- केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने धनवंतरि जयंती (धनतेरस) के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
- मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम की शुरूआत 30 अक्टूबर से होगी। इसके बाद 2 नवम्बर (धनतेरस) तक प्रदेशभर में आयुर्वेद दिवस से संबंधित कार्यक्रम होंगे।

संबल योजना

- संबल योजना के अंतर्गत सहायता राशि के 7 हजार 700 प्रकरणों में 170 करोड़ रूपए की राशि संबल हितग्राहियो के खातों में जमा की गई |
- इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु पर 02 लाख रूपए की राशि देने एवं अंतिम संस्कार के लिए 05 हजार रूपए की सहायता देने की व्यवस्था है।
- मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना 01 अप्रैल 2018 से आरंभ की गई है।
- संबल योजना में हितग्राही और उसके परिवार के सदस्यों को आंशिक स्थाई अपंगता पर 01 लाख और स्थाई अपंगता पर 02 लाख की सहायता प्रदान किये जाते है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम

- कोविड महामारी के दौरान देश में 18 लाख से अधिक नवीन जॉबकार्ड जारी किए गए।
- इस वित्तीय वर्ष में माह सितम्बर तक 76 लाख से अधिक ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया गया |
- अनुसूचित जनजाति के परिवारों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने में मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

- इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 52 जिलों के 45 हजार 135 ग्रामों में सघन रूप से कार्य किया जा रहा है।
- मिशन के माध्यम से करीब 53 हजार ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण तथा 2 लाख 86 हजार युवाओं को स्व-रोजगार प्रशिक्षण दिया गया है।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख 4 हजार से ज्यादा ग्रामीणों को स्व-रोजगार शुरू करने हेतु ब्याज रहित ऋण प्रदान किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में लग्भाग एक लाख 12 हजार 613 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय तथा 1,990 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 1,930 ग्रामों में घर-घर कचरा इकठ्ठा करने का कार्य और 15 हजार 445 सामुदायिक कम्पोस्टिंग के कार्य किये गए |
- स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में की गई थी ,जिसका उद्देश्य था गाँधी जी की 150 वीं जयंती (2 अक्टूबर 2019) तक भारत “खुले में शौच मुक्त “ बने

byjusexamprep